

141
12.3.17

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 13 जुलाई, 2017

विषय:- प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत पशुपालन विभाग हेतु अनुमोदित कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5870/पशुधन-तीन/आपदा-एस.पी.ए.-आर /2016-17, दिनांक 22.03.2017 के क्रम में पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या-01(15)/2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव जो वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत जनपद बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी की कुल 20 कार्ययोजनायें जिनकी परियोजना लागत ₹ 607.98 लाख है, के सापेक्ष नियोजन विभाग द्वारा इंगित ₹ 554.62 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विशेष योजनागत सहायता(पुनर्निर्माण) के अंतर्गत लेखानुदान मद में प्राविधानित धनराशि में से पशुपालन विभाग की नियोजन विभाग द्वारा इंगित परियोजनाओं हेतु ₹ 554.62 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने हेतु संलग्न सूची के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा, जो हाई पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिन पर धनराशि व्यय किये जाने की समस्त प्रकार की औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं और जो योजनायें मानकों के अनुरूप हों। किसी भी ऐसी योजना पर धनराशि व्यय नहीं की जायेगी जो हाई पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत नहीं है तथा ऐसी योजनाओं के सापेक्ष किसी भी धनराशि का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

3- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति

प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

5- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6- यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

7- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

8- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग/आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग/जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10- कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11- त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

12- विभागाध्यक्ष पशुपालन विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

14- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु विभागीय बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

15- स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं लेखांकन तथा लेखा परीक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष का होगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0104-एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013), मतदेय के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30, जून 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या-1457(1)/XVIII-(2)/17-04(15)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ का इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित परियोजनाओं का अपने स्तर से भी पर्यवेक्षण करते हुए नियमित रूप से आख्या शासन को उपलब्ध करायेगें।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़।
- 8- निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 9- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव

संलग्नक- शासनादेश संख्या:-/451/XVIII-(2)/17-04(15)/2015 दिनांक 13 जुलाई, 2017

Name of Department	Name of Projects	Total Project Cost	Amount Release by GOI for 2016-17 in lakhs
Animal Husbandry	1- Bageshwar		
	Construction of livestock Centre, Sorga and Reconstruction of Boundry wall of sheep farm.	29.95	28.35
	Construction of State sheep & wool Extension centere gogina	37.70	35.00
	Construction of State sheep & wool Extension centere baghar	36.57	35.00
	Construction of State sheep & wool Extension centere supi	32.26	30.00
	2. Chamoli		
	Repairing of roof of state vet. Hospital	1.65	1.65
	Repairing of Boundry of non residential building of livestock centre simli	28.82	25.00
	3- Pithoragarh		
	Construction of vety. Hospital khet (Dharchula)	25.38	25.00
	Constt. Of Boundry wall of state Poultry farm, Bin	58.12	55.00
	4- Rudraprayag		
	Construction of Vety. Hospital at Bagarwala Tok, Ukhimath	42.90	40.00
	Construction fof Vety. Hospital and Type- IV residence at Nala, Gptakashi	57.23	53.82
	5- Uttarakashi		
	Strengthening of vety, Hospital, Gyansu	19.72	17.00
	Reconstruction of Safely will of livestock Centre, Bagasu	15.05	10.00
	Construction of office building of intensive Poultry Dev. Scheme, Gyansu	24.08	20.00
	Constt. Of Livestock Centre, Ghatwal Dhar	35.06	30.00
	Constt. Of livestock Centre, Gadugad	58.43	55.00
	Constt. Of livestock Centre, Pujaragaon	31.34	25.00
	Constt. Of livestock Centre, Gadoli	32.46	30.00

	Constt. Of livestock Centre, Thalkundi	32.46	30.00
	Constt. Of labotary at vety. Hospital Chinyalisaur	3.80	3.80
	Maintenance works at Vety. Hospital Naitwad	5.00	5.00
	Total	607.98	554.62


 (अमित सिंह नेगी)
 सचिव